

सं०-287698/XXVII(10)/E-77990/2025

प्रेषक,

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/सचिव(प्र०),
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,
कुमौऊ/गढवाल मण्डल,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-10

देहरादून : दिनांक 01, मार्च, 2025

विषय:- राज्यान्तर्गत बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञानित कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-2 से 4 के मूल नियम-110 में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति में भेजे जाने संबंधी प्राविधान वर्णित हैं। राज्य गठन के पश्चात् इस सन्दर्भ में राज्यान्तर्गत स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं हैं, अपितु पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० के वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-जी-1-176/दस-99-53(46)-76 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 16.03.1999 के प्राविधानानुसार बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावों को निस्तारित किया जा रहा है। उक्त शासनादेश के कम में प्रशासकीय विभागों द्वारा 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिनियुक्ति अवधि को विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जाते हैं। राज्यान्तर्गत प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु समायवधि के निर्धारण एवं तत्संबंधी प्रकरणों में प्रायः विविध कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, तदनुसार राज्यान्तर्गत इस हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने आवश्यक है।

2- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यान्तर्गत प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1- परिभाषाएँ :-

क). बाह्य सेवा :- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(7) के अनुसार बाह्य सेवा का अर्थ है वह सेवा, जिसमें कर्मचारी अपना मौलिक वेतन शासन की स्वीकृति से निम्नलिखित द्वारा प्राप्त करता है :-

(क). केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा रेलवे बोर्ड के राजस्वों के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से।

(ख). स्टेट रेलवे चलाने वाली कम्पनी से।

ख). प्रतिनियुक्ति :- जब किसी कार्मिक को कैडर के बाहर से या पदोन्नति की सीधी रेखा के बाहर से सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके

अंत में उसे अपने मूल कैडर में वापस लौटना होगा, तो उसे प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध पर जाना जाता है। प्रतिनियुक्ति शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिकों को नियुक्त किया जाता है।

ग). सेवा स्थानांतरण :- कार्मिक विभाग के निर्गत शासनादेश सं०-490 दि० 21, दिसम्बर, 2015 के द्वारा कार्यहित में उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत राज्य के भीतर राज्य के एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में किसी कार्मिक की तैनाती सेवा स्थानांतरण है न कि प्रतिनियुक्ति।

2- अर्हता :- किसी कार्मिक के मौलिक नियुक्ति के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वह बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु अर्ह/पात्र होगा।

3- समयावधि :- बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु कार्यहित में सामान्य अवधि 03 वर्ष होगी, जिसे अग्रेत्तर 02 वर्षों हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही विस्तारित किया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी, जिसे किसी भी दशा में अग्रेत्तर विस्तारित नहीं किया जायेगा।

किसी कार्मिक द्वारा एक बार प्रतिनियुक्ति अवधि 03 वर्ष अथवा 02 वर्ष अथवा सम्पूर्ण 05 वर्ष, यथास्थिति पूर्ण करने के पश्चात् अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि कूलिंग पीरियड (Cooling off period) होगी, जिनके पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्मिक को आगे बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु उनके अनुरोध पर तैनात किये जाने हेतु यथाप्रकिया निर्णय लिया जायेगा। सम्पूर्ण सेवा काल में किसी भी कार्मिक को अधिकतम 02 बार ही बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अनुमन्य किया जा सकेगा।

जिन राजकीय विभागों में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु विभागीय ढाँचे में पद सृजित किये गये हैं, में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की सामान्य अधिकतम 5 वर्ष की सीमा के पश्चात् पैतृक विभाग, जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति की जानी है एवं संबंधित कार्मिक की सहमति होने पर उक्त समयावधि में वृद्धि किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनिवार्यतः निम्नवत् गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा :-

क्र०सं०	विवरण	पद
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्र०), कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव/सचिव(प्र०), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव/सचिव(प्र०), उत्तराखण्ड शासन (कार्मिक के पैतृक विभाग)।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव/सचिव(प्र०), उत्तराखण्ड शासन (जिस विभाग में कार्मिक को बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरित करना है)।	संयोजक सदस्य

यद्यपि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects (EAPs)) में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अधिकतम 5 वर्ष की सामान्य सीमा लागू नहीं होगी, तथापि उसका मध्यावधिक मूल्यांकन करने के पश्चात् पैतृक विभाग, जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति की जानी है एवं संबंधित कार्मिक की सहमति होने पर उसे अग्रेत्तर युक्ति-युक्त औचित्य के आधार विस्तारित किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4— सामान्य दिशा-निर्देश :-

1). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु सामान्य 03 वर्ष की अवधि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा संबंधित कार्मिक के स्थायीकरण, उनके मूल विभाग की अनापत्ति, कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक, प्रशासनिक, अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न होने संबंधी प्रमाण-पत्र आदि, सेवाभिलेखों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा। उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जायेगी कि विभागीय आवश्यकतानुसार संबंधित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है तथा तत्संबंधी आदेश निर्गत होने की तिथि से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

2). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु सामान्य 03 वर्ष की अवधि के पश्चात् अग्रेत्तर 02 वर्ष की अवधि की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित प्रस्ताव उक्त अवधि पूर्ण होने के 01 माह पूर्व जिस संस्था में कार्मिक की आवश्यकता हैं, के सक्षम अधिकारी का मांग पत्र (आवश्यकता का औचित्य सहित), संबंधित कार्मिक के मूल विभाग की अनापत्ति, जिसमें इस आशय की स्पष्ट संस्तुति उल्लिखित हो कि संबंधित कार्मिक के यथास्थिति बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण, पर जाने में शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होंगे, सहित प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिक की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तो संबंधित कार्मिक की उक्त अवधि स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं उन्हें तत्काल अपने मूल विभाग में योगदान किया जाना होगा।

बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

3). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के पश्चात् अनाधिकृत रूप से तैनात कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग के निर्गत शासनादेश सं0-4 जी0आई0, दि0 12, मार्च, 2007 के प्राविधानानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा उक्त अवधि नियमानुसार विस्तारित न होने की दशा में अवधि समापन की तिथि को वह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। संबंधित नियंत्रक अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनात कार्मिक को उनकी उक्त अवधि के समाप्त होने की दशा में तत्काल कार्यमुक्त करें अन्यथा उनका उत्तरदायित्व स्वतः सिद्ध हो जायेगा।

4). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनात कार्मिक के मूल विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से इस आशय की समीक्षा की जायेगी कि कोई कार्मिक

अनाधिकृत रूप से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी संबंधित संस्थाओं में तैनात तो नहीं हैं। ऐसी दशा में उनके द्वारा भी संबंधित कार्मिक को पत्र प्रेषित कर विभाग में योगदान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा, अन्यथा कि स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

5). जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्त में 05 वर्ष का समय अवशेष रह गया हो, ऐसे कार्मिकों को किसी भी दशा में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनाती नहीं प्रदान की जायेगी और यदि कोई कार्मिक पूर्व से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनात हैं एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष अवशेष रह गया हों, को अनिवार्य रूप से अपने मूल विभाग में योगदान कराया जाये एवं किसी भी दशा में ऐसे कार्मिकों की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि विस्तारित नहीं की जायेगी।

6). कार्यहित में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण मुख्यतः 02 प्रकार के पदों के सापेक्ष किये जाते हैं, प्रथम प्रकार के पद पूर्णतः प्रतिनियुक्ति के पद होते हैं तथा द्वितीय प्रकार के पद नियमित पद होते हैं, जिनमें नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने तक की अवधि के लिये कार्य संचालन प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किया जाता है।

उक्त दोनो पदों हेतु प्रक्रियानुसार बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर कार्मिक की तैनाती की जाती है, जिसमें उक्त हेतु शर्तों/प्रतिबंध वर्णित होते हैं। उक्त शर्तों/प्रतिबंधों में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अवधि का प्राविधान भी उल्लिखित होता है, किन्तु प्रायः उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जाती, अपितु तैनात कार्मिक की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अवधि को विस्तारित किये जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो उक्त पद पर अन्य पात्र कार्मिक की तैनाती के समानता के अवसर का हनन है। साथ ही विभागों द्वारा नियमित पदों पर ससमय नियुक्ति न करते हुए, प्रतिनियुक्त कार्मिक से ही शासकीय कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिससे उक्त कार्मिक उक्त पद पर अनाधिकृत अवधि तक बना रहता है एवं उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित न होने के कारण उनके मूल विभाग के शासकीय कार्य भी प्रभावित होते हैं।

समस्त विभाग इस परिपाटी के स्थान पर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अवधि को विस्तारित किये जाने की प्रक्रिया के विकल्प को अपनाये जाने से पूर्व प्रथम विकल्प के रूप में समानता के अवसर के सिद्धान्त को लागू किये जाने के दृष्टिगत उक्त पद हेतु पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे अन्यथा की स्थिति में द्वितीय विकल्प के रूप में विस्तारीकरण के विकल्प को अपनायेंगे।

3— उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by

Vadivel Shanmugam

Date: 01-04-2025 15:14:41 (डा. वी. वी. शनमुगम)

भवदीय,

सचिव

-3-

सं०-287698/XXVII(10)/E-77990/2025, तददिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, सचिव-मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव-मा० वित्त मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

Signed by

Vijay Kumar

Date: 01-04-2025 15:38:48

आज्ञा से,

(विजय कुमार)

संयुक्त सचिव